(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) A quantity of 9.97 lakh MTs of wheat valued at Rs. 648.17 crores CIF (approximate) has been imported so far during the year 1997-98. Against the contract already signed a balance quantity of 7.50 lakh tonnes valued at Rs. 475.86 crores CIF approximately is expected to arrive at Indian ports by January/ February 1998.

(b) and (c) Minimum Support Price (MSP) for wheat is fixed by the Government after considering the recommendations made by the Commission for Agricultural Costs & Prices which takes into consideration the cost of cultivation of wheat and a reasonable margin of returns to the farmers while recommending MSP. Government announced the MSP of wheat at Rs. 415 per quintal for the marketing year 1997-98. Thereafter the Government also decided that the farmers would be paid a Central bonus of Rs. 60 per quintal during 1997-98 for procurement from 1.4.97 to 30.6.97 in addition to the MSP. Recently, the Government has announced the MSP for wheat at Rs. 455 per quintal for the marketing year 1998-99. The MSP fixed serves as a guarantee to the producer that in the event of a glut in the market due to excess production or otherwise the prices will not be allowed to fall below the minimum economic levels. Further, the farmers are free to sell their produce in the open market at prices higher than those fixed by the Government.

Import of wheat on Government account is resorted to, to augment its availability in the country and, therefore, it is not proper to compare MSP/ procurement price with cost of imported wheat.

पंजाब को आबंटित खाद्य वस्तुएं तथा उनकी मात्रा

487. **श्री इकबाल सिंहः** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा पंजाब राज्य को किन-किन वस्तुओं का तथा कितनी-कितनी मात्रा में आवंटन किया गया है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान पंजाब राज्य को सभी वस्तुओं का कम आवंटन करने के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) पंजाब राज्य को पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा चावल, गेहूं, चीनी और मिट्टी के तेल का आवंटन किया गया था। तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित आवंटन और उठान हुए हैं:—

(हजार टन में)

जिन्स	1994-95	1995-96	1996-97
चावल			
आवंटन	17.25	16.65	18.00
उठान	1.30	2.00	1.60
गेहूं			
आवंटन	210.00	155.00	121.00
उठान	1.50	8.00	54.00
चीनी			
आवंटन	99.25	101.00	109.96
उठान*			
मिट्टी का तेल			
आवंटन	325.68	328.93	335.95
उठान	324.00	329.87	307.38

*उठान 100 प्रतिशत माना गया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त विवरण से यह देखा जा सकता है कि खाद्यान्नों का उठान आवंटन से कम हुआ है। अतः कम आवंटन का प्रश्न नहीं उठता। चीनी का आवंटन 1991 की जनगणना के आधार पर 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह के एक समान मानदण्ड पर किया जाता है। पंजाब के लिए मिट्टी के तेल का आवंटन पहले ही प्रति व्यक्ति के रूप में राष्ट्रीय औसत से अधिक है।